भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2737

उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

उत्तराखंड में उच्च शिक्षा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

2737 # **श्री महेंद्र भट्टः**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तराखंड के केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत ढांचे, शोध सुविधाओं और डिजिटल शिक्षा में सुधार करने के लिए पिछले पांच वर्षों में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) आगामी वर्षों के लिए क्या योजना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्थान हैं और ये विश्वविद्यालय उनके अंतर्गत बनाए गए अपने अधिनियमों, संविधियों, अध्यादेशों और विनियमों आदि से शासित होते हैं तथा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। शिक्षा मंत्रालय "केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान" के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को ब्लॉक अनुदान जारी करता है, जिसके परिणामस्वरूप आयोग बाद में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (एचएनबीजीयू) उत्तराखंड सहित प्रत्येक केंद्रीय विश्वविद्यालय को उनकी आवश्यकताओं, विगत वर्षों में निधियों के उपयोग आदि के आधार पर निधियों का आबंटन करता है। विगत पांच वर्षों (अर्थात वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक) के दौरान अवसंरचनात्मक सुधार के लिए पूंजी शीर्ष (ओएच-35) के अंतर्गत एचएनबीजीयू, उत्तराखंड को 33.53 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) भी कार्यान्वित कर रहा है, जो केंद्रीय प्रायोजित एक योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निधि प्रदान करना है, ताकि निर्दिष्ट मानकों और मानदंडों की अनुपालना को सुनिश्चित करते

हुए उनकी गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 12,926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तीसरे चरण का आरंभ किया है। पीएम-उषा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस योजना को 31 मार्च, 2028 तक एवं रूसा की जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 6 माह (अर्थात 30 सितंबर, 2026) तक और बढ़ा दिया गया है।

वर्ष 2013 में रूसा की शुरुआत होने के बाद, 161.60 करोड़ रुपये की लागत के साथ पीएम-उषा के अंतर्गत अनुमोदित 8 परियोजनाओं सहित उत्तराखंड राज्य हेतु 427.74 करोड़ की लागत के साथ कुल 74 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। विगत पांच वर्षों के दौरान, चालू वित्त वर्ष 2026-27 (दिनांक 10.08.2026 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान 26.19 करोड़ रुपये सहित केंद्रीय हिस्सा के रूप में राज्य को कुल 136.88 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 में विशेषकर एसटीईएम संस्थानों में उच्चतर शिक्षा तक पहुँच में सुधार के लिए प्रत्येक ज़िले में एक बालिका छात्रावास स्थापित करने और मूल शिक्षा तक पहुँच हेतु अवसंरचना के रूप में किफायती छात्रावास क्षमता के सृजन का प्रस्ताव रखा है।

****